आइआइएम की शोध रिपोर्ट

हरित अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र बन सकता है अपना झारखंड

झारखंड सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करनेवाले राज्यों में अग्रणी बन सकता है. यहां मौजूद वन, खनिज, नदियां और विविधता भरी जनजातीय समुदाय राज्य को एक बेहतर "हरित अर्थव्यवस्था" से लाभान्वित कर सकती हैं. राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए खनन पर निर्भरता के अलावा भी वैकल्पिक श्रोत हैं. इसमें वन उपज और उत्पादन को शामिल किया जा सकता है. सतत विकास के दृष्टिकोण से झारखंड में कृषि-वानिकी (एग्रोफॉरेस्ट्री) – मौसम अनुकूल फसल व पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपीएस) मौसमी फल और मेवे, सब्जियां, औषधीय पौधे, रेजिन, बांस, ताड़ के पेड़, घास व मछली जैसे संभावित विकल्पों को जागृत कर व्यवस्थित अर्थव्यवस्था में ढाला जा सकता है. इस पर नीतिगत काम हो, तो जनजातीय समुदायों को व्यवस्थित रोजगार देकर उनकी आजीविका में बदलाव लाया जा सकता है.

प्रो मनीष बंसल

चेयरपर्सन, डॉक्टोरल प्रोग्राम एंड रिसर्च, आइआइएम, रांची

इस दिशा में चुनौतियां भी हैं. जबकि खनन पर अत्याधिक निर्भरता ने राज्य को सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याओं की ओर धकेल दिया है. नीति आयोग कि ओर से जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में झारखंड को 100 में 62 अंक मिले, जो संभावनाओं और परिणामों के बीच की बढ़ती दूरी को दर्शाता है. इसके अलावा भुखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानताओं जैसे लक्ष्यों में भी झारखंड का प्रदर्शन चिंतनीय रहा. यह सभी राज्य के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

हरित अर्थव्यवस्था के बड़े अवसर : सतत विकास पर केंद्रित नीतियों में रोजगार एक बड़ा विषय है. इस ओर देखा जाये, तो हरित अर्थव्यवस्था को राज्य में स्थापित कर बेहतर अर्थव्यवस्था की सीढ़ी तैयार की जा सकती है. राज्य की भौगोलिक स्थिति सौर, पवन और बॉयोमास ऊर्जा को विकसित करने की अपार क्षमता रखती है. यह संसाधन के रूप में उभरे तो लोगों तक हरित रोजगार के रूप में पहुंचेगी. साथ ही राज्य का कोयला और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घट सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन के लिए सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स को गठन किया है. जिसका उद्देश्य उपयुक्त जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था को विकसित करना है. यह आगे चल कर स्वच्छ ऊर्जा समाधान, कार्बन बाजार और हरित प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दे रही है.

इसके अलावा राज्य के पास कार्बन क्रेडिट भी एक अवसर है, जो सघन वन संपदा, बायोमास और मिट्टी में कार्बन अवशोषण के माध्यम से कार्बन क्रेडिट तैयार कर सकता है. इससे स्थानीय समुदायों के लिए आय का नया श्रोत तैयार होगा. इसकी रूपरेखा तय करने के लिए राज्य को कार्बन क्रेडिट वेरिफिकेशन सिस्टम और इससे जुड़ा बाजार तंत्र विकसित करना होगा, जो वैश्विक स्तर पर कार्बन ऑफसेट बाजार – जहां कंपनियां अपनी उपयोगिता अनुरूप कार्बन क्रेडिट पर निवेश कर सकेगी.

प्रभात खबर के पाठकों के लिए तैयार रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

1. झारखंड के पास वन, खनिज, नदियों और जनजातीय विविधता के कारण हरित अर्थव्यवस्था का केंद्र बनने की क्षमता
2. खनन पर अत्यधिक निर्भरता ने सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय क्षरण की समस्याएं बढ़ायी हैं
3. नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में झारखंड को 100 में 62 अंक मिले हैं
4. कृषि-वानिकी और गैर-लकड़ी वन उत्पाद राज्य की वैकल्पिक आर्थिक ताकत बन सकते हैं
5. जनजातीय समुदायों को इन क्षेत्रों में रोजगार देकर उनकी आजीविका सशक्त की जा सकती है
6. सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा के विकास से राज्य हरित रोजगार सृजित कर सकता है

डेटा आधारित निगरानी और नीति समन्वय से मिलेगी सफलता

झारखंड की वर्तमान परिस्थिति और भविष्य में सतत विकास के लक्ष्यों के लिए नीतिगत रूप से राज्य को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड तैयार करने की जरूरत है. जो, राज्य व जिला स्तर के आंकड़ों को समेकित कर वास्तविक विकास की स्थिति समय पर व पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करा सके. डेटा संग्रहण के लिए राज्य के पास पहले से ही व्यवस्था व उपकरण मौजूद है, जबकि इसे व्यवस्थित व सशक्त करने पर नीतिगत प्रयास करने होंगे. इससे न केवल बेहतर योजना बल्कि राज्य के जनजातीय समुदायों की मदद से विकास यात्रा को रफ्तार मिलेगी.